International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 28-08-2021; Accepted: 07-09-2021; Published: 09-09-2021
Volume 3, Issue 2, 2021, Page No. 17-26

अफगानिस्तान में तालिबान: समस्या या समाधान

डॉ अश्वनी शर्मा[1], शशि शेखर प्रसाद सिंह[2]

[1] एसोशिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, सत्यवती कॉलेज, नई दिल्ली, भारत

[2] असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, सत्यवती कॉलेज, नई दिल्ली, भारत

सारांश

9/11 की आतंकवादी घटना के बाद विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए) के नेतृत्व में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की सेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हवाई हमले तथा सैनिक कार्रवाई करके आतंकवादी संगठन 'तालिबान' को 2001 के अक्तूबर में सत्ता छोडकर भागने को मजबूर कर दिया था। तब अंतराष्ट्रीय राजनीति के अध्येताओं ने कल्पना भी नहीं की थी कि दो दशक बाद वही तालिबान अमेरिकी सेना की काबुल के हामिद करज़ई एयरपोर्ट पर उपस्थिति के बावजूद यू एस समर्थित राष्ट्रपति अशरफ गनी सरकार की तीन लाख से अधिक संख्या वाली सुरक्षा सेना के बिना प्रतिरोध के काबुल की सत्ता पर दुबारा नियंत्रण कर लेगा। यदपि विश्व को चौकाने वाली यह राजनीतिक घटना तालिबान की नाटकीय सैन्य सफलता के रूप में देखा जा रहा है किन्तु इसके पीछे अमेरिका और तालिबान के बीच 29 फरवरी, 2020 को कतर की राजधानी दोहा में सम्पन्न शांति समझौता का बहुत कूटनीतिक महत्व है। अफगानिस्तान में महाशक्तियों के बीच जारी विश्व में बर्चस्व की लड़ाई में सोवियत संघ के सैनिक हस्तक्षेप और अन्तत: खाली हाथ वापसी तथा, अब 2021 में 20 वर्षों बाद यू एस के द्वारा अफगानिस्तान को उसी तालिबान को सौंपकर वापसी दो महाशक्तियों की अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप की विफलता ही दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। क्या तालिबान इस बार अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता स्थापित कर वहाँ के आम जनता, और खासकर लड़कियों, औरतों को सुरक्षा, सम्मान और विकसित होने का अवसर दे पाएगा और दक्षिण एशिया में आतंकवाद को बढ़ावा न देकर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित तनाव को और नहीं बढ़ाएगा? ऐसे कई सवालों के संभावित उत्तर को जानने और समझने की कोशिश यह शोध पत्र करता है।

मूल शब्द: संयुक्त राज्य अमेरिका, अल-कायदा, तालिबान

प्रस्तावना

अफगानिस्तान में दो दशक बाद कट्टरपंथी इस्लामिक तालिबान के द्वारा शक्ति के बल पर सत्ता पर नियंत्रण इतिहास की पुनरावृति है। पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिद्वंदी समाजवादी महाशक्ति सोवियत संघ की सेना की 1989 में अफगानिस्तान की धरती से वापसी के बाद वहाँ लगातार राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध की स्थिति रही (Uma Shankar, 2008)। 1996

से 2001 तक पाँच वर्षो के लिए तालिबान का काबुल पर सैन्य नियंत्रण रहा लेकिन सऊदी अरब के नागरिक ओसामा बिन लादेन के द्वारा निर्मित इस्लामिक आतंकवादी संगठन 'अल-कायदा' द्वारा 9/11 को यू एस ए के न्यूयार्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दो अपहृत विमानों से आतंकवादी विस्फोट की घटना तथा एक अन्य अपहृत विमान के विस्फोट से अमेरिकी सेना के मुख्यालय पेंटागन को भी क्षति पहुंचाई गयी और एक अन्य अपहृत विमान से पेंसिल्वानिया राज्य में भी विस्फोट हुआ। एक ही दिन 9/11 को हुई आतंकवादी घटनाओं में तीन हज़ार लोग मारे गए। अचानक इन आतंकवादी घटनाओं से पूरी दुनिया अचंभित थी और अमेरिका तथा पश्चिमी जगत में गुस्से और आक्रोश का माहौल था। यू एस ए के तत्कालीन रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लयू बुश ने तालिबानियों को सख़्त शब्दों में चेतावनी देते हुए इन आतंकवादी विस्फोटों के लिए जिम्मेदार संगठन के मुखिया ओसामा बिन लादेन और काबुल की सत्ता पर नियंत्रण किये बैठी इस्लामी संगठन तालिबान के प्रमुख मुल्ला उमर को तुरन्त अमेरिका को सौपने की मांग की (Kevin Liptak, cnn.com, August 24, 2021)। साथ ही मांग न मानने की स्थिति में सैनिक कार्रवाई की धमकी दी। तालिबान के द्वारा इन मांगों को न मानने पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के देशों की सेना के साथ मिलकर 7 अक्तूबर,2001 को "आपरेशन एंडयूरिंग फ्रीडम" (Kevin Liptak, cnn.com, August 24, 2021) के नाम से तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर दिया। इसका प्रतिफल था कि 2001 के अंत के पूर्व ही अफगानिस्तान पर 1996 से चला आ रहा तालिबानी सैन्य नियंत्रण का अंत हो गया। अब तालिबान के उस काल को तालिबान के नियंत्रण के इस काल से अलग समझने के लिए तालिबान 1.0 और तालिबान 2.0 के रूप में देखा जा रहा है।

यह सच है कि अमेरिका तथा गठबंधन सहयोगी देशों ने 9/11 की आतंकवादी घटनाओं की तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में अफगानिस्तान की धरती से आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के उद्देश्य से सैनिक हस्तक्षेप किया था ताकि भविष्य में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी आतंकवादी आक्रमण की घटनाओं की पुनरावर्ती न हो सके। इसके लिए आवश्यक था कि अफगानिस्तान में तालिबान तथा अल-कायदा विरोधी राज्य व्यवस्था हो और अमेरिका को इसमें आरंभिक राजनीतिक सफलता भी मिली किन्तु जातीय संघर्ष और युद्ध मसीहाओं की उपस्थिति वाले अति पिछड़े अफगानिस्तान में यह कार्य निसंदेह आसान नहीं था। यू एस ए और गठबंधन देशो की सहयोगी सेनाएँ वर्षो हवाई हमले और सैनिक कारवाई के बाद भी राजधानी काबुल के बाहर सुदूर तथा पाकिस्तान और मध्य एशिया के देशो की सीमाओं से सटे इलाकों से तालिबान तथा कुछ अन्य इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकी संगठनों के प्रभाव को खत्म नहीं कर पाई (William Dalrymple, BBC News, 9 March, 2014)। परिणामतः अमेरिका अफगानी सरकार को अफगानिस्तान की सुरक्षा सौपकर वापस जाना चाहती थी और इसके लिए अफगानिस्तान में शांति स्थापना के कूटनीतिक प्रयास करना चाहती थी। 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने ये स्वीकार कर लिया कि अमेरिका का उद्देश्य अफगानिस्तान में 'राष्ट्र निर्माण' कभी नहीं था और न 'एकीकृत, केंद्रीयकृत लोकतंत्र' की स्थापना ही (Remarks by President on Afghanistan, whitehouse.gov, August 16, 2021)। इसी दिशा में प्रयास करते हुए खाड़ी के देश 'कतर' की राजधानी 'दोहा' में यू एस ए ने राज्येतर पात्र आतंकवादी संगठन तालिबान को तो 'शांति समझौता' वार्ता में शामिल कर लिया था किन्तु तालिबान के दबाव में राज्यरूपी पात्र अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी सरकार को शांति वार्ता में शामिल न करके उसकी वैधता पर खुद ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। 'दोहा शांति समझौता' के बाद अमेरिकी ने 29 फरवरी, 2020 को दो दशक बाद आगामी 1 मई, 2021 तक अफगानिस्तान

से सेना की वापसी की घोषणा कर दिया । 'दोहा शांति समझौता' वार्ता में तालिबान का शामिल होना और अफगानी सरकार को वार्ता से बाहर रखा जाना अफगानिस्तान के राजनीतिक भविष्य का संकेत तो देने लगा था और यह लगने लगा था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के लिए काबुल पहुँचने का रास्ता साफ हो रहा है (Amb Anil Trigunayat, www.vifindia.org/2021/august20) किन्तु सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा और इस्लामी जिहादी तालिबान प्रकाश गति से काबुल पर अमेरिकी सेना की काबुल के करज़ई हवाई अड्डे पर होने के बावजूद कब्जा कर लेगा, यह तो विश्व राजनीति तथा अफगान विशेषज्ञों के लिए भी चौकाने वाली घटना थी । यहाँ तक कि अमेरिकी इंटेलिजेंस भी धोखा खा गयी और इस बात की पुष्टि का प्रमाण 8 जुलाई, 2021 का राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रैस कॉन्फ्रेंस में दिया गया वक्तव्य है जिसमें उन्होनें साफ शब्दों में कहा था कि अफगान सरकार अभी नहीं गिरेगी और तालिबान लो काबुल पहुँचने में कम से कम तीन महीने तो लगेंगे ही (President Biden, whitehouse.gov, July 8,2021)।

अब जो सवाल सामने है- क्या तालिबान का काबुल पर सैन्य नियंत्रण अफगानिस्तान में एक संप्रभु राज्य का निर्माण कर राजीनीतिक स्थिरता स्थापित कर पाएगा, क्या अफगानिस्तान में तालिबान का फिर से राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण दुनिया की राजनीति में अमेरिकी एकाधिकारवाद के अंत के शुरुआत की सूचना है, क्या तालिबान 2.0 का अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात की स्थापना दक्षिण एशिया में तनाव को बढ़ाएगा, क्या तालिबान की सख़्त इस्लामी शरीयत के कानून और अन्य जातीय समूहों के प्रति भेदभाव पूर्ण राज्य आचरण से अफगानिस्तान में मानवीय संकट बढ़ेगा और अफगानी जनता के बड़े हिस्से को पड़ोसी देशो तथा अन्य देशो में शरणार्थी बनने के लिए बाध्य करेगा ....? यद्यपि इन महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालों का उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में है लेकिन राजनीति चाहे, स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय हो या अंतराष्ट्रीय, है तो संभावनाओं का खेल और उसका अध्ययन इसलिए इनके संभावित उत्तर को जानने के लिए अफगानिस्तान के संक्षिप्त इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था तथा राजनीति को समझना जरूरी है।

राजधानी काबुल पर तालिबान का नाटकीय सैन्य नियंत्रण

अफगानिस्तान के विषय में एक प्रसिद्ध कहावत है – अफगानिस्तान साम्राज्यवादियों की कब्रगाह है । अभी तक अफगानिस्तान में उत्तर-द्वितीय विश्व युद्ध के काल में अंतराष्ट्रीय राजनीति की दोनों महाशक्तियों का अलग अलग काल खंड में सैन्य हस्तक्षेप की घटना और उसके अंतिम राजनीतिक परिणाम इस कथन की पुष्टि करते हैं। उदाहरणस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सालों, खासकर महाशक्तियों के बीच तनाव शैथिल्य के दौर में यदि अफगानिस्तान के राजनीतिक इतिहास पर दृष्टिपात किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि सोवियत सैन्य हस्तक्षेप महाशक्तियों के बीच दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत के लिए उत्तरदायी था और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के हस्तक्षेप का दस वर्षों बाद अंतिम परिणाम, और अब अमेरिकी एकाधिकारवाद के दौर में पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी वैश्विक महाशक्ति के अंतिम सैनिक की वापसी के पूर्व ही अफगानिस्तान में उसकी सैन्य शक्ति के साये में समर्थित सरकार का अंत भी विश्व के सामने है।

तालिबान 2.0 ने जिस नाटकीय तरीके से 10 दिनों के अंदर (BBC News,18 August,2021) अफगानिस्तान के 80% भूभाग पर सैन्य शक्ति के बल से कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जहां अमेरिकी तथा गठबंधन देशो की सेनाएँ हामिद करज़ई एयरपोर्ट पर स्वदेश वापसी के क्रम में 6-7 हजार की संख्या में मौजूद थी और राष्ट्रपति जो बाईडन की घोषणा

के अनुसार उन्हें 31 अगस्त तक काबुल की धरती से अंतिम रूप में जाना था किन्तु तालिबान को काबुल पर नियंत्रण करने की ऐसी चाहत थी कि उसने 31 अगस्त की भी प्रतीक्षा नहीं किया और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा करते हुए 15 अगस्त को राजधानी काबुल पर (BBC News,18 August, 2021) बिना अफगानी सुरक्षा सेना के किसी प्रतिरोध के राष्ट्रपति भवन तक को कब्जा करने में सफल हो गए। आश्चर्य की बात यह थी कि अफगानिस्तान के चुने हुए राष्ट्रपति अशरफ गनी जो एक दिन पूर्व तक राष्ट्र के नाम सम्बोधन में पूरे विश्वास के साथ तालिबान से अफगान सुरक्षा सैनिकों के मुक़ाबले की बात कर रहे थे (Nayanima Basu, The Print, 21 August, 2021) वो तालिबान के काबुल में प्रवेश करने के ठीक पूर्व रहस्यमय तरीके से अपने कुछ विश्वासपात्र सहयोगियों के साथ काबुल छोडकर ही नहीं, देश छोडकर भाग गए (Nayanima Basu, The Print, 21 August, 2021) और अफगानी सुरक्षा सेना को नेतृत्वविहीन तथा दिशाहीन छोड़ गए। संकट के समय देश से पलायन करने के बाद अपने फैसले को उचित ठहराते हुए उनका एक वक्तव्य आया कि देश को रक्तपात से बचाने के लिए उन्होने ऐसा कदम उठाया (India Today Web Desk, August 16, 2021)। वहीं दूसरी तरफ उनके प्रथम उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अफगानिस्तानी इस्लामिक गणराज्य के संविधान (Article 67, Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan, 2004) का हवाला देते हुए राष्ट्रपति के देश छोडकर जाने के बाद खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित करते हुए अफगानिस्तान के उत्तर में स्थित हिन्द कुश की पर्वतमालाओं से घिरे तंज़शीर से तालिबान के परंपरागत घोर विरोधी अहमद मसूद के उत्तरी गठबंधन के साथ मिलकर तालिबान बिरोधी मोर्चा बनाकर नए तालिबानी शासकों को चुनौती देने की बात की है (The Week, 17 August, 2021)। उत्तरी गठबंधन पहाड़ियों से घिरे तंज़शीर की घाटियों से तालिबान को कितनी चुनौती दे पाएगा, यह तो आनेवाला कल बताएगा।

इस प्रकार बीस वर्षों से काबुल की सत्ता से दूर हिंसा और आतंकी गतिविधियों में संलग्न तालिबान ने दस दिनों में तख़्ता पलट दिया। चौकाने वाला तथ्य यह है कि दो दशकों से अमेरिकी सेना के नेतृत्व में गठबंधन की सेना अफगानिस्तान में अफगानी राज्य, सुरक्षा सेना, पुलिस तथा मानवीय सेवा और विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने में लगी रही और तालिबानी जिहादियों की तुलना में लगभग चौगनी, बेहतर सैन्य प्रशिक्षित तथा आधुनिक तकनीकों से युक्त सैन्य उपकरणों से सुसज्जित अफगानी सुरक्षा सेना (President Biden, whitehouse.gov, July 8, 2021) की उपस्थिति के बावजूद तालिबान महज कुछ दिनों में कंधार से हेरात पर कब्जा करते हुए काबुल पहुँच गए। यह अमेरिकी राज्य की दो दशकों की अफगानी राज्य निर्माण के कोशिश के खोखलेपन को दुनिया के सामने उजागर करता है क्योंकि आखिरकार इन 20 वर्षों में अमेरिका ने तालिबान को तालिबान से बदल दिया (Amb Anil Trigunayat,www.vifindia.org/2021/august/20)। यहाँ तक कि अमेरिकी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन भी काबुल पर तालिबान के आनन-फानन में सैन्य नियंत्रण के बाद अपने प्रैस कॉन्फ्रेंस में अचंभित नजर आए और उनके चेहरे पे और शब्दों में अमेरिका के दो दशकों के प्रयास की विफलता की स्वीकारोक्ति साफ दिखी, यद्यपि उन्होने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी अफगान सरकार की तीन लाख प्रशिक्षित सुरक्षा सेना की थी। आखिर जिस अफगानिस्तान को कट्टरपंथी इस्लामी तालिबानियों से मुक्त कराने के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए, लगभग 2500 हज़ार अमेरिकी सैनिकों की कुर्बानी दी, उसका अंजाम क्या निकला ? सच तो ये है कि तालिबान 2,0, तालिबान 1.0 की तुलना में अधिक शक्तिशाली होकर सामने आए हैं और तालिबान को जन्म और जीवन दे वाले पाकिस्तान की गुप्तचर सेवा आई एस आई के स्थायी समर्थन, प्रशिक्षण, संरक्षण के अलावे

दुनिया के कई शक्तिशाली देशों- चीनी जनवादी राज्य, रूसी संघ सहित कई अन्य खाड़ी क्षेत्र के सऊदी अरब, सऊदी अरब अमीरात, यहाँ तक कि ईरान आदि एशियाई देशों से राजनीतिक समर्थन जुटाने में सफल हुए हैं जबकि तालिबानियों ने 'अफगानिस्तानी इस्लामी गणराज्य' का नाम बदलकर 'अफगानिस्तानी इस्लामी अमीरात' घोषित कर दिया, राष्ट्रीय झंडे को बदल, तालिबानी झंडे को राष्ट्रीय झण्डा बना दिया और अफगानी संविधान को अमेरिकी वर्चस्व की विरासत समझकर निरस्त कर दिया।

तालिबान की राजनीतिक अग्नि परीक्षा

प्रश्न उठता है कि 20 वर्षों से जिस अफगानी राज्य का वजूद था, जिस झंडे से विश्व समुदाय में उसकी पहचान थी, सब समाप्त हो गया। दुनिया के मानचित्र पर अब अफगानिस्तान एक ऐसे देश के रूप में विद्यमान है जो सरकार विहीन इस्लामिक कट्टरपंथियों के नियंत्रण में है और अफगान नागरिक, खास करके महिलाएं एवं बच्चों का जीवन और भविष्य संकट में है। ऐसा इसलिए है कि दुनिया और अफगानी जनता 1996 से लेकर 2001 तक के तालिबान के क्रूर, निर्मम, मानव अधिकार विरोधी कट्टर इस्लामिक जिहादी फरमानों और महिला विरोधी शासन को भूली नहीं है और लाखों जीवित अफगानी नागरिकों की स्मृतियों में यह नासूर के रूप में मौजूद है। अतः तालिबान 2.0 एक स्थिर, वैधानिक प्रभुता सम्पन्न अफगानिस्तान का निर्माण कर पाएगा और महिलाओं सहित अफगानी नागरिकों को जीवन, स्वतन्त्रता तथा उसकी संपत्ति की रक्षा कर संगठित तथा वैध राज्य का निर्माण कर पाएगा, ऐसा तालिबान 1.0 के डरावने कार्यकाल को देखकर नहीं लगता। यद्यपि तालिबान 2.0 ने काबुल पर सैन्य नियंत्रण के बाद एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की कि अफगान नागरिकों को डरने की आवश्यकता नहीं है, महिलाओं को काम करने से रोका नहीं जाएगा और तालिबान अफगानिस्तान के भूभाग पर आतंकवाद को कोई संरक्षण नहीं देगा इसलिए दुनिया के देशों को इसबार तालिबान से डरने की कोई जरूरत नहीं है (Zee Media Bureau, August 17, 2021)।

यहाँ यह स्वाभाविक संदेह होता है कि तालिबान जिसका इतिहास इस्लामिक जिहाद से जुड़ा है और जो एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है और जिसकी आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय रहने की वैश्विक पहचान है और जिसमे मूलतः एक खास पश्तुन जातीय समुदाय के लोग शामिल हैं, वह अफगानिस्तान के अन्य जातीय संगठनों के बीच एकता स्थापित करके समावेशी अफगानी राज्य बना पाएगा और उसमे सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएगा क्योंकि तालिबान एकमात्र इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन नहीं जो अफगानिस्तान में सक्रिय है। सोवियत संघ के सैन्य हस्तक्षेप के सैन्य प्रतिरोध के दिनों से कई अन्य इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन भी सक्रिय हैं और उनमे परस्पर हिंसक शक्ति संघर्ष भी है, सत्ता की लड़ाई में उनके बीच जो प्रतिद्वंदिता है, क्या वह समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, पंजशीर की घाटी तालिबान विरोधी अहमद मसूद के उत्तरी गठबंधन के नियंत्रण में है जो तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण को अस्वीकार कर उसे खुली चुनौती दे रहा है। यह वही उत्तरी गठबंधन है जिसने तालिबान 1.0 के खिलाफ यू एस तथा सहयोगी देशों की सेना का खुलकर साथ दिया था। यह 'अफगानिस्तानी इस्लामी गणराज्य' को पुनर्स्थापित करने की मांग कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या उत्तरी गठबंधन तालिबान 2.0 से कोई सम्झौता कर 'अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात' राज्य निर्माण में अपनी किसी भूमिका के लिए कभी तैयार होगा ? तालिबान 2.0 के लिये इन सैन्य तथा राजनीतिक चुनौतियों का समाधान जरूरी है। इसलिए अफ़गानी राज्य के लिए आवश्यक है कि विभिन्न प्रतिद्वंदी जातीय संगठनों के बीच संघर्ष के बजाय संवाद से एकता स्थापित हो।

तालिबान 2.0 के समक्ष अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की

गंभीर चुनौती है। अबतक अफगानी अर्थव्यवस्था मूलतः बाहरी देशो की आर्थिक मदद पर निर्भर रहा है। सोवियत संघ के हस्तक्षेप से पूर्व ही यह सोवियत सहायता पर टिकी थी, सोवियत संघ के विरुद्ध संघर्ष में अमेरिका तथा अन्य पश्चमी देशों ने भरपूर आर्थिक सहायता दी और अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप के बाद अमेरिकी आर्थिक सहायता सुरक्षा और पुनरसंरचना का आधार बन गया। अफीम की खेती को कई क्षेत्रों में अफगानी लोगों और आतंकवादी संगठनों ने अपने आय का स्रोत बना लिया। तब कैसे तालिबान 2.0 राज्य तथा शासन के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन अपने बलबूते जुटा पाएगा, यह मुश्किल सवाल है।

इतना ही नहीं, अफगानी जनता के एक बड़े हिस्से में यह विश्वास पैदा कर पाएगा कि तालिबान 2.0 लोगों के जीवन की सुरक्षा के साथ साथ उसकी संपत्ति की हिफाजत करेगा, उनके बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगार का इंतजाम करेगा और विकास को प्राथमिकता मिलेगी। ये बहुत मुश्किल सवाल हैं और इनका कोई उत्तर अभी तालिबान के पास नहीं है। अभी तक तालिबान एक सरकार का गठन नहीं कर पाया है। बंदूक की गोली के बल पर शासन पर कब्जा तो किया जा सकता है किन्तु बंदूक के बल पर जनता का विश्वास और उनके लिए विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। तालिबान ने काबुल पर फिर कब्जा करने के बाद जो घोषणाएँ की हैं और जनता के साथ साथ जो दुनिया को आश्वस्त करने की जो कोशिश की है, उसकी सच्चाई की परख होनी अभी बाकी है। अमेरिका के विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकेन ने ठीक ही कहा है कि तालिबान को अभी अंतराष्ट्रीय वैधता तथा सहायता अर्जित करना होगा (Blinken, thehill.com, 30 August, 2021)। अभी का कड़वा सच तो यह है कि अफगानी जनता तालिबानी बंदूक के साये में डरी सहमी जी रही है। काबुल के हवाई अड्डे पर अफगानिस्तान छोडकर जाने की ख्वाइश लिए लाखों अफगानी नागरिक जिस प्रकार व्याकुल और हताश देखे गए, उससे साफ लगता है कि तालिबान 2.0 ने अफगानिस्तान पर जबरन कब्जा तो कर लिया किन्तु उसके लिए राज्य व्यवस्था और सरकार चलना आसान नहीं होगा। तालिबान ने साफ शब्दो में कहा है कि इस्लामिक शरीयत कानून (Zee Media Bureau, August 17,2021) के द्वारा शासन चलाया जाएगा और लोकतन्त्र जैसी कोई व्यवस्था उसे कतई स्वीकार नहीं। ऐसी स्थिति में अराजक राजनीति और जर्जर अर्थव्यवस्था बिना अफगानी जनता की भागीदारी के कैसे स्थिर और सुरक्षित हो पाएगी – इन सवालो के उत्तर दूर भविष्य के गर्भ में है।

महाशक्तियों का शक्ति संघर्ष और अफगान राजनीति पर प्रभाव

अफगानिस्तान की भोगोलिक स्थिति, उसका सामरिक महत्व विश्व की महाशक्तियों को आकर्षित करता रहा है। परिणामतः अफगानिस्तान का राजनीतिक संकट कोई आज का नहीं। यदि दूर अतीत में न जाकर शीत युद्ध के दौर में समाजवादी महाशक्ति सोवियत संघ का 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप (Hindustan Times, 4 January, 1980) और उसके बाद 10 वर्षों तक अफगानिस्तान में रूस समर्थित सरकार को बचाए रखने की तमाम कोशिश विफल हो गयी। अंततः सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोब के द्वारा जेनेवा समझौता (Vinod Chopra, 1988) के बाद अफगानिस्तान की धरती से सोवियत संघ लगभग निराश और पराजित 1989 में लौट गया। अपने आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे सोवियत संघ के लिए अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप एक दुस्साहसिक फैसला था और अफगानिस्तान से सेना वापसी के दो वर्ष के अंदर विश्व का पहला समाजवादी देश 1991 में विघटित होकर 15 नए देशो में बदल गया। सोवियत संघ के विघटन में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप एक

महत्वपूर्ण बाह्य कारक था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के विरुद्ध पूंजीवादी अमेरिका तथा पाकिस्तान सहित उसके सहयोगी देशों ने जिस प्रकार से अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों को एकत्रित कर युद्ध सामाग्री तथा आर्थिक सहायता देकर सोवियत नेतृत्व को अफगानिस्तान से सेना वापस करने के लिए बाध्य कर दिया और जेनेवा समझौते के बाद सोवियत सेना किसी तरह इज्जत बचाकर चली गयी (Uma Shankar, 2008, p. 223)। यह सोवियत संघ जैसी महाशक्ति के लिए अपमान और पराजय की स्थिति थी।

यद्यपि सोवियत संघ अफगानिस्तान में समाजवादी विचारों पर आधारित आधुनिक अफगानी राज्य का निर्माण करने में विफल रहा किन्तु सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिका ने इस्लामिक जिहादियों जैसे कई कट्टरपंथी संगठनों को पैदा कर दिया। सऊदी अरब के इस्लामिक सोच से प्रभावित सऊदी अरब का अमेरिका में शिक्षित ओसामा बिन लादेन जिसने अल-कायदा का गठन किया। पाकिस्तानी सैनिक शासकों ने मदरसा में धार्मिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों से तालिबान को पैदा कर दिया और विभिन्न जनजातीय समूहों ने अमेरिकी और उसके सहयोगी देशो के समर्थन से मुजाहिदिनों की फौज खड़ी कर दी और सोवियत संघ की सेना तथा उसकी अंतिम समर्थित नजीबुल्लाह की 1992 तक चली सरकार के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। अब यही इस्लामिक जिहादी शक्तियाँ अफगानिस्तान में किसी आधुनिक राज्य निर्माण में सबसे बड़ी बाधा बन गयी है। अल-कायदा और तालिबान ऐसे ही आतंकवादी संगठन थे जो सोवियत संघ के समाजवादी विचारों के विरुद्ध मध्यकालीन इस्लामिक राज्य का निर्माण अपना उद्देश्य समझते थे और वही पूंजीवादी अमेरिका के अस्त्र और धन से रक्त और मज्जा पाकर अमेरिकी पूंजीवादी राज्य के खिलाफ भी इस्लामिक राज्य निर्माण को ही अपना मकसद मानते हैं। अमेरिका ने खुद 9/11 की आतंकवादी घटना को भुगता। कहते हैं जो शेर को पालते हैं वो कभी खुद शेर का भी शिकार बन जाते हैं। आखिरकार अपने ही द्वारा निर्मित आतंकवादी संगठनों के द्वारा शिकार होने पर अमेरिका को नाटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान के तालिबानी शासन के खिलाफ अक्तूबर 2001 में सैनिक कारवाई करनी पड़ी और इसप्रकार अमेरिका तालिबान को राजधानी काबुल से भगाने में कामयाब रहा किन्तु लंबे अंतराल के बावजूद अमेरिका से जो अपेक्षा थी कि अमेरिका तमाम आतंकवादी संगठनों को समाप्त कर अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र तथा मजबूत राज्य बनाने और विकसित करने में साकारात्मक भूमिका निभाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे तालिबान जैसी कट्टरपंथी ताक़तें फिर से संगठित होने लगी और अफगानिस्तान के दूर दराज इलाकों तथा पाकिस्तान से या पाकिस्तान की सीमा से जुड़े इलाकों से पाकिस्तान की आई एस आई के सैन्य तथा आर्थिक सहायता से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देकर अमेरिका समर्थित काबुल की सरकार के समक्ष सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पेश करती रही। सच्चाई तो यह भी है कि अमेरिका क्रमशः तालिबान को खत्म करने के बजाय उससे संवाद के द्वारा किसी शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान की तलाश करने लगा। इससे तालिबान का मनोबल बढ़ा और उसकी स्वीकारोक्ति भी बढ़ी। दूसरी तरफ दोहा समझौता वार्ता से अफगानिस्तान की सरकार को बाहर रखने से उसकी वैधता जो पहले से संदेह के घेरे में थी और कम हो गयी। अब उसका परिणाम भी सामने है जब 20 वर्षों बाद वही तालिबान लगभग बिना किसी प्रतिरोध के आसानी से 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने में सफल हो गया। यह अमेरिकी प्रयासों की विफलता की कहानी कहता है, हालांकि राष्ट्रपति ऐसा नहीं मानते (Remarks by President Biden on Afghanistan, whitehouse.gov, August 16, 2021) और दुनिया के सामने यह एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों की सहायता और संरक्षण से एक

राज्य का निर्माण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस देश के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, जनजातीय या अन्य सामुदायिक समूहों को संगठित कर तथा उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कर राज्य का निर्माण नहीं किया जाता। यह तालिबान जैसी कट्टरपंथी ताकतों की जीत से अधिक अमेरिका जैसी साम्राज्यवादी ताकतों की पराजय का उदाहरण है। वियतनाम में अमेरिकी साम्राज्यवाद के पतन के बाद अफगानिस्तान में जहां अमेरिका का सैनिक हस्तक्षेप सबसे अधिक रहा, आखिरकार अमेरिका के अंतिम सैनिक के वापसी के पूर्व ही उसकी वर्षों से समर्थित सरकार कुछ ही दिनों में रेत की दीवार की तरह ढह गया। यह दक्षिण एशिया से लेकर मध्य एशिया में अमेरिकी प्रभाव के कम होने का प्रमाण है। इराक से लेकर लीबिया और सीरिया में अमेरिकी सैन्य शक्ति कोई स्थायी प्रभाव स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया है और ऐसा लगता है कि पूंजीवादी अमेरिका की एकाधिकारवादी शक्ति अब चीनी जनवादी गणराज्य और रूसी संघ की बढ़ती चुनौतियों के कारण पराभव की ओर अग्रसर हो रहा है।

दक्षिण एशिया पर काबुल पर तालिबानी नियंत्रण का प्रभाव

दक्षिण एशिया में तालिबान के अफगानिस्तान पर सैन्य नियंत्रण से तनाव बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित कई कारणों से निरंतर तनाव के कारण काबुल में तालिबान की उपस्थिति तथा पाकिस्तान और तालिबान के बीच मधुर रिश्ता भारत और पाकिस्तान में विद्यमान तनाव को और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिस प्रकार तालिबान के द्वारा सैन्य नियंत्रण को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति (The Times of India, August 16, 2021) का नाम दिया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ अपने मजबूत समर्थन से भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। कश्मीर में अफगानिस्तान की धरती से आतंकवादी ताकतों को महबूती मिल सकती है। यह भूला नहीं जा सकता कि तालिबान 1.0 के काल में ही भारतीय यात्री विमान को अपहरण करके पाकिस्तानी आतंकवादी कांधार ले गए थे और भारत की तत्कालीन एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को यात्रियों के जीवन की रक्षा के लिए बाध्य होकर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन खूंखार आतंकवादी को काबुल ले जाकर छोडना पड़ा था।

इतना ही नहीं, चीन दक्षिण एशिया में अपने राजनैतिक, आर्थिक तथा सैनिक प्रभाव के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इधर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लगातार बढ़ा है और सैनिक झड़प तक हुई है। वैसे में जिस प्रकार से चीन बढ़ चढ़ कर तालिबान को समर्थन दे रहा है और ' मित्रता और सहयोग' की बात कर रहा है (The Guardian, 3 September, 2021), उससे से लगता है कि दक्षिण एशिया में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलकर भारत के हितों के लिए नया संकट पैदा करने की कोशिश कर सकता है। ऐसी स्थिति में काबुल में तालिबान की उपस्थिति से दक्षिण एशिया में तनाव के बढ़ने से इंकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि कश्मीर सहित भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादी घटनाओं के बढ़ने से भी इंकार नहीं किया जा सकता। आतंकवाद के संदर्भ में यह भी विचारणीय प्रश्न है कि अमेरिका जो अफगानिस्तान में भारी मात्रा में सैनिक साजो सामान अफगानिस्तान में तालिबान के लिए छोडकर चला गया उसका इस्तेमाल किस प्रकार होगा। तालिबान इस्लामिक जिहाद में विश्वास करता है, लोकतान्त्रिक मूल्यों, नागरिक स्वतन्त्रता और मानव अधिकारों के मूल्यों से उसका कोई सरोकार नहीं, ऐसी स्थिति में निसंदेह वह लोकतान्त्रिक ताकतों को नहीं,

आतंकवादी शक्तियों को ही समर्थन देगा और मजबूती भी प्रदान करेगा जो दक्षिण एशिया, खासकर भारत के लिए चिंता कारण है। अफगानिस्तान में भारत वहाँ के विकास और पुनरसंरचना के लिए करोड़ों का निवेश कर चुका था वे सारे प्रोजेक्ट छोडकर भारतीय दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों को भागना पड़ा।

यह भी संभावना है कि दक्षिण एशिया में अगर चीन का प्रभाव बहुत बढ़ता है तो यह अमेरिका और रूस के लिए भी चिंता पैदा करेगा और हो सकता है कि अमेरिका, रूसी संघ दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के कोई कदम उठाए जो दक्षिण एशिया की सुरक्षा और शांति को खतरा पहुंचा सकता है। किसी भी स्थिति में अफगानिस्तान में तालिबान भारत के लिए शुभ संकेत नहीं।

निष्कर्ष

अमेरिका ने सोवियत संघ के सैन्य हस्तक्षेप के विरुद्ध कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों को पैदा किया था और मजबूत किया था तथा उन्हीं की सहायता से सोवियत संघ की सेना को अफगानिस्तान से वापस लौटने को बाध्य किया था। किन्तु यह भी सच है कि तालिबान जैसी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन ने अमेरिका को 20 वर्षों बाद अफगानिस्तान की धरती से जाने को बाध्य कर विश्व की दोनों महाशक्तियों जिन्होंने सैनिक हस्तक्षेप के बाद अलग अलग समय पर अफगानिस्तान को समाजवादी या पूंजीवादी राज्य बनाने की कोशिश की, के मंसूबे पर पानी फेर दिया। अब तालिबान 2.0 के काबुल पर नियंत्रण के बाद अफगान की जनता का भविष्य क्या है जबकि दुनिया के कट्टरपंथी इस्लाम के समर्थकों ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत को इस्लाम की जीत माना और पूंजीवादी साम्राज्यवादी अमेरिका की हार। इतना ही नहीं, इसे अफगानिस्तान की स्वतन्त्रता के रूप में देखा किन्तु क्या इसे आम अफगानी की आजादी के रूप में देखा जा सकता है। तालिबान ने अफगानिस्तानी इस्लामिक गणराज्य को अफगानिस्तानी इस्लामिक अमीरात घोषित कर दिया और संविधान की जगह इस्लामिक शरीयत कानून को लागू कर दिया। आज अफगानी जनता के सामने स्वचालित आग्नेयास्त्र लेकर घूमते तालिबानी तो हैं किन्तु कोई सरकार नहीं। यहाँ तक कि समाचार पढ़ने वाले एंकर के पीछे भी स्वचालित शस्त्र के साथ तालिबानी खड़े हैं तो ऐसा लगता है तालिबान अफगानिस्तान में एक इस्लामी फासीवादी राज्य की स्थापना करना चाहता है ...

Reference

1. Uma Shankar, State Building in Afghanistan; Linkage with International Politics, (Academic Excellence, Delhi), 2008.
2. Kevin Liptak, Bush Obama, Trump Biden. How four presidents created today’s Afghanistan mess, https://www.cnn.com,August 24, 2024.
3. William Dalrymple. Is Afghanistan really impossible to conquer https://www.bbcnews.com,9 March,2014
4. Remarks by President Biden on Afghanistan, www.whitehouse.gov, August 16, 2021.
5. Amb Anil Trigunayat, https://www.vifindia.org/2021/august20/lost-in-afghnistan
6. Remarks by President Biden on the Drawdown of U.S.Forces in Afghanistan www.whitehouse.gov, July 8, 2021
7. BBC News, https://www.bbcnews.com, 18 August, 2021.
8. Nayanima Basu, The Print, https://theprint.in, 21 August, 2021.
9. India Today Web Desk, https://www.indiatoday.in,16 August, 2021.
10. Constitution of the Islamik Republic of Afghanistan, Art 67, 2004.
11. The Week, https://www.theweek.in, 17 August, 2021.
12. Zee Media Bureau. https://zeenews.india.com,17 August, 2021.
13. Blinken: Taliban must earn legitimacy and support, https://www.thehill.com, 30 August, 2021.

14. Hindustan Times, 4 January, 1980.
15. Vinod Chopra (Ed) Afghanistan: Geneva Accord and After,(Patriot Pub, New Delhi) 1988.
16. The Times of India,16 August, 2021.
17. The Guardian, 3 September, 2021.